

## एनबीएफसी क्षेत्र के नवीनतम कार्य-प्रदर्शन का विश्लेषण

अभ्युदय हर्ष, नंदिनी जयकुमार,  
रजनीश कुमार चंद्रा और ब्रिजेश पी. ^ द्वारा

वैश्विक वित्तीय संकट के बाद उल्लेखनीय रूप से विस्तार करते हुए, एनबीएफआई वैश्विक वित्तीय संरचना में अपरिहार्य दल के रूप में उभरे हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में जटिल वित्तीय बाजार संरचना में कार्य करने वाली एनबीएफआई के विपरीत, भारत में एनबीएफसी ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं के बीच अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट मध्यस्थता की भूमिका निभाती हैं। हालांकि, हाल के दिनों में इस क्षेत्र के बढ़ते आकार और परस्पर संबंध के कारण विनियामकीय बदलाव की जरूरत पड़ी। एनबीएफसी क्षेत्र की समेकित बैलेंस शीट ने दिसंबर 2022 के अंत में दहाई अंकों की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि का प्रदर्शन किया। हालांकि उनकी लाभप्रदता में मामूली कमी आई है, लेकिन इस क्षेत्र ने मजबूत पूंजी भंडार बनाए रखना जारी रखा है। महामारी के कारण डिजिटल सेवाओं के उपयोग में तेजी आई है जिससे एनबीएफसी के समक्ष अवसर और चुनौतियां, दोनों आ पड़ी हैं।

### भूमिका

हाल के वर्षों में, विशेष रूप से 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद, गैर-बैंक वित्तीय संस्थाएं (एनबीएफसी) वैश्विक वित्तीय प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक के रूप में उभरी हैं। आकार और अंतर्संबंध के संदर्भ में उनकी वृद्धि, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) के साथ-साथ उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) दोनों में एक प्रमुख विशेषता बन गई है। वर्ष 2002 में लगभग 57 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से उनका आकार तेजी से बढ़कर वर्ष 2021 में 239 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है (एफएसबी, 2022)। जीएफसी के बाद बैंकों की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने वाले विनियामक परिवर्तन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन के कारण पेंशन निधि के प्रबंधन की आवश्यकता, तकनीकी परिवर्तन और परिचालन दक्षता की खोज

^ लेखक आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग से हैं। यह आलेख श्री गोपीनाथ प्रह्लाद चर तुलसी, परामर्शदाता के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों को नहीं दर्शाते हैं।

- इस संरचनात्मक बदलाव के पीछे मूलभूत बल थे (अरामोटे, श्रिम्प, और शिन, 2022)।

एनबीएफसी की गतिविधियां व्यापक और विविध हैं। बैंकों के विपरीत, उनके कार्यों को सख्ती से वर्गीकृत नहीं किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से, एनबीएफसी के पास सांविधिक सार्वजनिक बैकस्टॉप तक पहुंच नहीं थी और केंद्रीय बैंकों की बैलेंस शीट तक उनकी पहुँच या तो सीमित थी या बिल्कुल न के बराबर थी (अरामोटे, श्रिम्प, और शिन, 2022)। हालांकि, शेष वित्तीय प्रणाली के साथ उनकी अन्योन्याश्रितता के कारण, वे वित्तीय मध्यस्थता के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रणालीगत जोखिम पैदा कर सकते हैं, जो बैंकों पर लागू होने वाले विवेकपूर्ण मानकों को दरकिनार कर सकते हैं और समष्टि विवेकपूर्ण नीतियों सहित नीतियों की प्रभावकारिता को कम कर सकते हैं।

भारत में उनकी वृद्धि और वित्तीय स्थिरता के लिए प्रभाव को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों<sup>2</sup> (एनबीएफसी) के लिए स्केल-आधारित विनियमन<sup>1</sup> (एसबीआर) प्रस्तुत किया। एसबीआर में अपनाए गए दृष्टिकोण में एनबीएफसी के विनियमन के आनुपातिकता के सिद्धांत पर आधारित होने की परिकल्पना की गई है, जहां विनियम एनबीएफसी के आकार, गतिविधि और कथित जोखिम का एक फंक्शन है। वर्ष 2022 में, रिजर्व बैंक ने उच्च स्तर में रखे गए एनबीएफसी की ऋण जोखिम सघनता की जांच के लिए विवेकपूर्ण दिशानिर्देश भी जारी किए। वित्तीय स्थिरता के परिप्रेक्ष्य के अलावा, एनबीएफसी वित्तीय समावेशन उद्देश्य को साकार करने में प्रमुख भागीदारों में से हैं। दिसंबर 2022 के अंत में सकल सूक्ष्म ऋण पोर्टफोलियो में 38.5 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ, एनबीएफसी-एमएफआई ने अग्रणी सूक्ष्म-ऋण प्रदाता के रूप में बैंकों को पीछे छोड़ दिया (एमएफआईएन, 2022)।

शेष आलेख निम्नलिखित खंडों में विभाजित है: खंड II एनबीएफसी के अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य का संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है। खंड III भारत में एनबीएफसी क्षेत्र का एक सामान्य

<sup>1</sup> आरबीआई अधिसूचना दिनांक 22 अक्टूबर 2021, "स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए एक संशोधित विनियामक ढांचा"।

<sup>2</sup> इस आलेख में एनबीएफसी आरबीआई द्वारा विनियमित गैर-बैंकों को संदर्भित करते हैं, जैसा कि आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत परिभाषित किया गया है।

अवलोकन प्रदान करता है, जिसके बाद खंड IV है जो एनबीएफसी के ऋण के क्षेत्रवार वितरण, लाभप्रदता और आस्ति गुणवत्ता के साथ बैलेंस शीट पर चर्चा करता है। खंड V अन्य एनबीएफसी की तुलना में, एनबीएफसी की एक महत्वपूर्ण श्रेणी यथा मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) की भिन्न व्यावसायिक संरचना के आलोक में विचार-विमर्श करता है। आलेख का अंतिम खंड उभरती चुनौतियों पर कुछ निष्कर्षों के साथ समाप्त होता है।

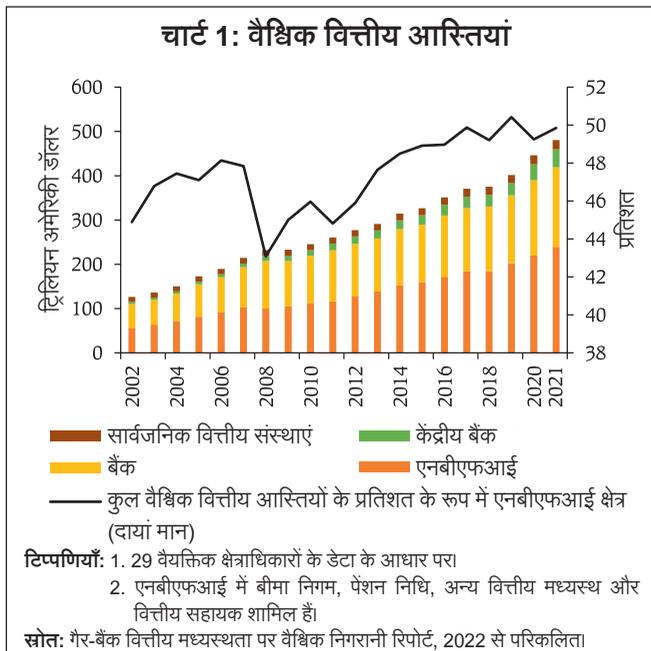
## II. वैश्विक परिप्रेक्ष्य

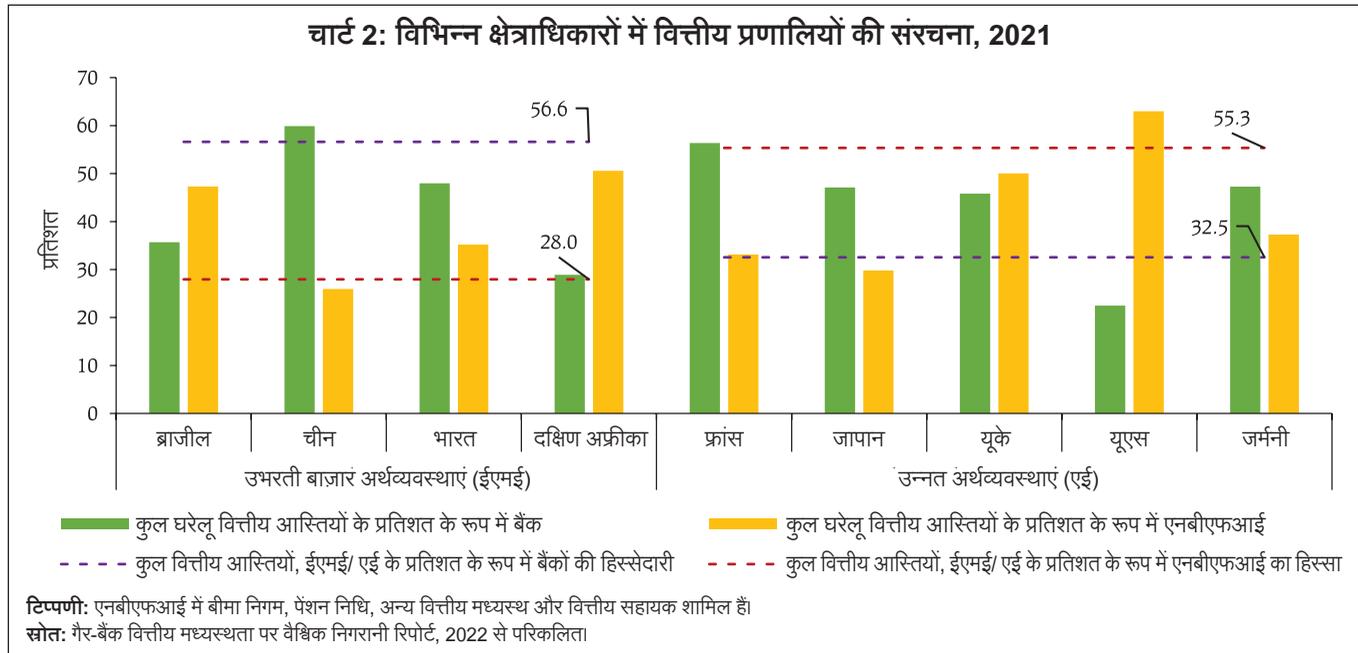
वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद विस्तार करते हुए एनबीएफआई वैश्विक वित्तीय संरचना में अपरिहार्य दल के रूप में उभरे हैं। उनमें संस्थाओं का एक विविध और जटिल समूह शामिल है, जो क्षेत्राधिकारों में अपने कारोबार मॉडल और कार्यों में व्यापक रूप से भिन्न हैं। समय के साथ वे अन्य वित्तीय संस्थाओं और संबंधित निहितार्थों के साथ अपने परस्पर संबंध के कारण नीतिगत चर्चाओं में ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे हैं। इस संबंध में, वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) इस क्षेत्र की वार्षिक निगरानी करता है तथा रुझानों, उभरते जोखिमों और नवोन्मेषों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जो हमें विभिन्न क्षेत्राधिकारों में एनबीएफसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

कोविड-19 महामारी के प्रकोप ने केंद्रीय बैंकों, बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के लिए अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों को आवश्यक समर्थन और स्थिरता प्रदान करने के लिए एक बड़ी भूमिका की आवश्यकता हुई। इसके परिणामस्वरूप 2020 में कुल वित्तीय आस्तियों में एनबीएफसी की हिस्सेदारी में मामूली गिरावट आई। हालांकि, 2021 में वैश्विक वित्तीय आस्तियों के प्रमुख चालक के रूप में एनबीएफसी फिर से सबसे आगे आ गए हैं, जो 9 प्रतिशत की दर से बढ़ रहे हैं, जो कुल में से लगभग आधी हिस्सेदारी है (चार्ट 1)।

हालांकि एनबीएफसी क्षेत्र की हिस्सेदारी पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ी है, लेकिन उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के वित्तीय परिदृश्य में बैंकों का वर्चस्व बना हुआ है, जो 2021 में उनकी वित्तीय आस्तियों का लगभग 57 प्रतिशत है। इसके विपरीत, उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ (ईई) में एनबीएफसी क्षेत्र प्रबल है। हालांकि, ईएमई और ईई दोनों के भीतर काफी विविधता मौजूद है, जैसे ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में एनबीएफसी क्षेत्र अधिक प्रभावशाली है, और फ्रांस और जापान जैसे ईई में बैंक-प्रभुत्व वाली अर्थव्यवस्थाएँ हैं (चार्ट 2)। वैश्विक स्तर पर, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) में एनबीएफआई की सबसे बड़ी उपस्थिति है और अन्य बड़े ईई के साथ इसके पास सबसे बड़ी और सबसे परस्पर संबद्ध एनबीएफआई यानी केंद्रीय प्रतिपक्ष, बचाव निधि (हेज फंड) और निवेश निधि हैं (अल्डासोरो, हुआंग और केम्प, 2020)।

वित्तीय प्रणाली में अन्य संस्थाओं के साथ उनके परस्पर संबंध के कारण, एनबीएफआई द्वारा उत्पन्न कमजोरियों की सीमा का बेहतर ढंग से पता लगाने के लिए, एफएसबी ने एक 'संकीर्ण उपाय (नैरो मीजर)' विकसित किया है। इस उपाय में ऋण मध्यस्थता गतिविधियों में लिप्त उन एनबीएफसी को शामिल किया गया है जिससे बैंक-जितने गम्भीर वित्तीय स्थिरता जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। यह माप पांच आर्थिक कार्यों (ईएफ) या गतिविधियों की एक संरचना है। दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्राधिकारों में, संकीर्ण उपाय अलग-अलग रूप लेता है, जो अर्थव्यवस्था-विशिष्ट आवश्यकताओं, नीति समर्थन और मौजूदा कानूनी और विनियामक संरचनाओं को दर्शाता है (एफएसबी, 2022)। परिणामस्वरूप, संकीर्ण माप के भीतर, ईएफ1 की विश्व स्तर पर सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, जिसका श्रेय





ईई में अच्छी तरह से विकसित और जटिल वित्तीय बाजार संरचनाओं को जाता है। भारत में एनबीएफसी अंतिम उधारदाताओं और अंतिम उधारकर्ताओं के बीच अधिक स्पष्ट मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं। वे उन व्यक्तियों और व्यवसायों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जो पारंपरिक बैंकिंग क्षेत्र द्वारा वंचित या कम सेवा प्राप्त हैं, और इस तरह वित्तीय

समावेशन और अंतिम व्यक्ति तक पहुँच की सुविधा प्रदान करते हैं। नतीजतन, भारत में गैर-बैंकिंग क्षेत्र को बड़े पैमाने पर ईएफ2 के तहत दर्शाया गया है (सारणी 1)।

वैश्विक स्तर पर 2021 में एनबीएफआई क्षेत्र की 9 प्रतिशत की कुल वृद्धि के अनुरूप, संकीर्ण माप में 9.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि भारत में संकीर्ण माप में 15.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई,

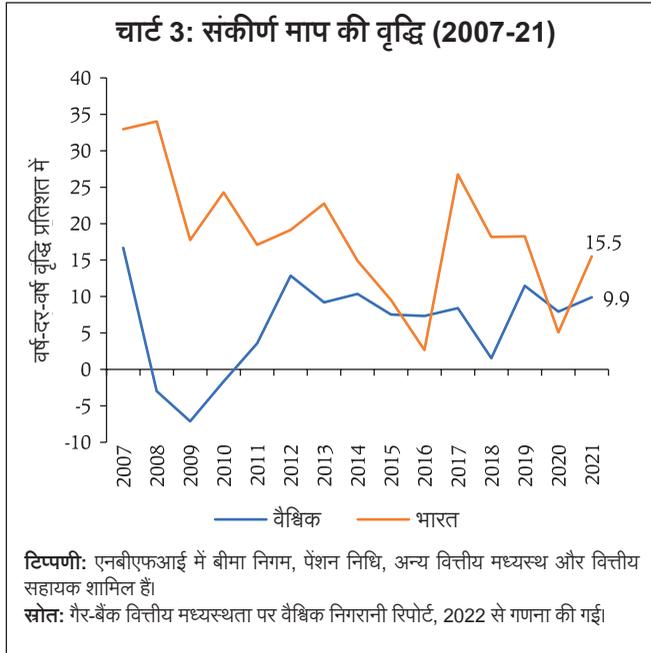
**सारणी 1: इकाई-प्रकार और गतिविधि के आधार पर संकीर्ण माप का वर्गीकरण, 2021**

आर्थिक कार्य/ गतिविधि	इकाई प्रकार	संकीर्ण माप में आर्थिक कार्यवार हिस्सेदारी: वैश्विक	संकीर्ण माप में आर्थिक कार्यवार हिस्सेदारी: भारत
ईएफ1	मुद्रा बाजार निधि, नियत आय निधि, मिश्रित फंड, क्रेडिट हेज फंड, रियल एस्टेट फंड	76.2	24.0
ईएफ2	वित्त कंपनियाँ, लीजिंग/फैक्टरिंग कंपनियाँ, उपभोक्ता ऋण कंपनियाँ	6.8	75.3
ईएफ3	ब्रोकर-डीलर, कस्टोडियल खाते, प्रतिभूति वित्त कंपनियाँ	6.8	0.4
ईएफ4	ऋण बीमा कंपनियाँ, वित्तीय गारंटीकर्ता, मोनोलाइन इश्योरर	0.2	0.0
ईएफ5	प्रतिभूतिकरण वाहन, संरचित वित्त वाहन, आस्ति-समर्थित प्रतिभूतियाँ	7.5	0.4
अनाबंटित	अन्य वित्तीय मध्यस्थों को एनबीएफआई से बैंक जैसी वित्तीय स्थिरता जोखिमों में शामिल होने का आकलन किया गया है, लेकिन जिन्हें एक विशिष्ट आर्थिक कार्य नहीं सौंपा जा सका है	2.4	0.0
संकीर्ण माप अर्थात्, ईएफ1+ईएफ2+ईएफ3+ ईएफ4+ईएफ5+अनाबंटित, कुल एनबीएफआई क्षेत्र की हिस्सेदारी के रूप में		28.3	42.7

**टिप्पणियाँ:** 1. 29 वैयक्तिक क्षेत्राधिकारों के डेटा पर आधारित, जिसमें आठ यूरो क्षेत्र क्षेत्राधिकार भी शामिल हैं, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 80 प्रतिशत हिस्सा है और जिसके लिए अधिक विस्तृत डेटा उपलब्ध था।

2. सूचीबद्ध इकाइयाँ संपूर्ण नहीं हैं, बल्कि विशिष्ट उदाहरण दर्शाती हैं।

**स्रोत:** गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता, 2022 पर वैश्विक निगरानी रिपोर्ट से परिकलित।



जो भारत के एनबीएफसी क्षेत्र में वृद्धि की तुलना में लगभग 5 प्रतिशत कम है (चार्ट 3)। भारत में एनबीएफसी क्षेत्र की एक रूपरेखा अगले खंड में प्रदान की गई है।

### III. भारत में एनबीएफसी क्षेत्र का एक सामान्य अवलोकन

भारत में एनबीएफआई में अलग-अलग बिजनेस मॉडल पर काम करने वाली विभिन्न प्रकार की संस्थाएं शामिल हैं। इस क्षेत्र के व्यापक आयाम को व्यवस्थित रूप से कवर करने के लिए, हमने एनबीएफआई को दो समूहों के तहत वर्गीकृत किया है: एक रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित और शेष अन्य विनियामकों, यथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), केंद्र या राज्य सरकारें द्वारा विनियमित है (चार्ट 4)।

रिजर्व बैंक के विनियामकीय दायरे में आने वाली इकाइयों में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एआईएफआई), सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं (एफआई) हैं जो कृषि, विदेश व्यापार, लघु उद्योगों, आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) और इंफ्रास्ट्रक्चर को दीर्घकालिक वित्त पोषण प्रदान करते हैं। आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) विशेषीकृत वित्तीय संस्थाएं हैं जो दबावग्रस्त

आस्तियों के समाधान के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से उन्हें खरीदकर एक संस्थागत विकल्प प्रदान करती हैं। एचएफसी देश में आवास गतिविधि का समर्थन करने के लिए व्यक्तियों, सहकारी समितियों और कॉर्पोरेट निकायों को आवास वित्त प्रदान करने में विशेषज्ञ हैं। प्राथमिक व्यापारी (पीडी) जी-सेक बाजार में बाजार निर्माताओं के रूप में कार्य करने के अलावा, सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) के प्राथमिक निर्गम के लिए सदस्यता सुनिश्चित करते हैं। एनबीएफसी में ज्यादातर प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां शामिल हैं जो ऋण वितरण और वित्तीय मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

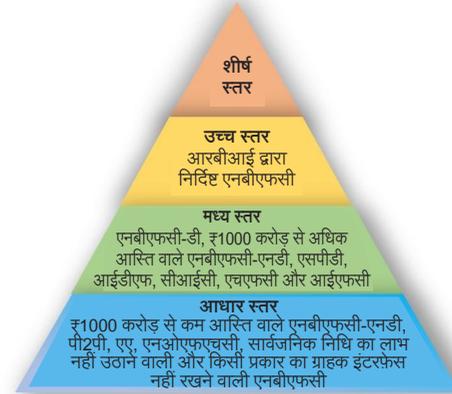
एनबीएफसी की शुरुआत 1940 के दशक के उत्तरार्ध में हुई थी जब कई लघु वित्त कंपनियों ने टर्कों की खरीद के लिए निधियन की पेशकश की थी (कन्नन, शनमुगम और भादुड़ी, 2019)। समय के साथ वे पूर्ण रूप से वित्तीय संस्थाओं के रूप में विकसित हुए, जिन्होंने ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप पारंपरिक और नवीन वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करके उन बाजार क्षेत्रों में प्रवेश करने में विशेषज्ञता विकसित की, जहां बैंकों की उपस्थिति कम थी। इसके अलावा, उन्हें बैंकों के संबंध में अलग-अलग विनियमन से लाभ हुआ है, जिससे उन्हें नवोन्मेष को बढ़ावा देने और बैंकों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रदान करने की

अनुमति मिलती है, जिससे अंततः अंतिम ग्राहकों को लाभ होता है। भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में एनबीएफसी क्षेत्र के बढ़ते महत्व को देखते हुए, शेष आलेख में 2022-23 में दिसंबर 2022 तक चुनिंदा एनबीएफसी के प्रदर्शन का वर्णन है और यह उन्हें अक्टूबर 2022 से प्रभावी एसबीआर ढांचे के संदर्भ में समूहीकृत करता है।

एसबीआर ढांचे के तहत, एनबीएफसी चार स्तरों में से एक में रखे जाते हैं, अर्थात् शीर्ष (एनबीएफसी-टीएल), उच्च (एनबीएफसी-यूएल), मध्य (एनबीएफसी-एमएल) या आधार स्तर (एनबीएफसी-बीएल) [चार्ट 5]। अभी के लिए शीर्ष स्तर को खाली रखा गया है और यदि रिजर्व बैंक, एनबीएफसी-यूएल में विशिष्ट एनबीएफसी से संभावित प्रणालीगत जोखिम में पर्याप्त वृद्धि देखता है तो इस स्तर में एनबीएफसी रखे जाएंगे।

मार्च 2022 के अंत में, संख्या के संदर्भ में लगभग 94 प्रतिशत एनबीएफसी, एनबीएफसी-बीएल श्रेणी के तहत थे, जबकि आस्ति आकार के संदर्भ में, एनबीएफसी-बीएल कुल आस्ति आकार का केवल 5 प्रतिशत था (चार्ट 6)। इस क्षेत्र में बाजार संकेंद्रण की प्रकृति को देखते हुए, जहां लगभग 6 प्रतिशत

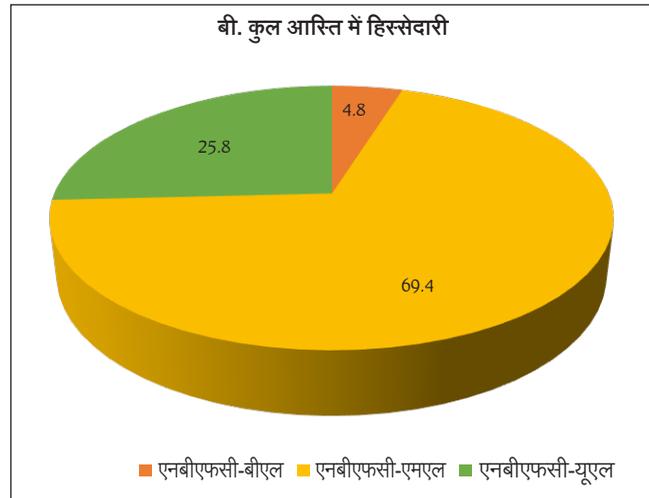
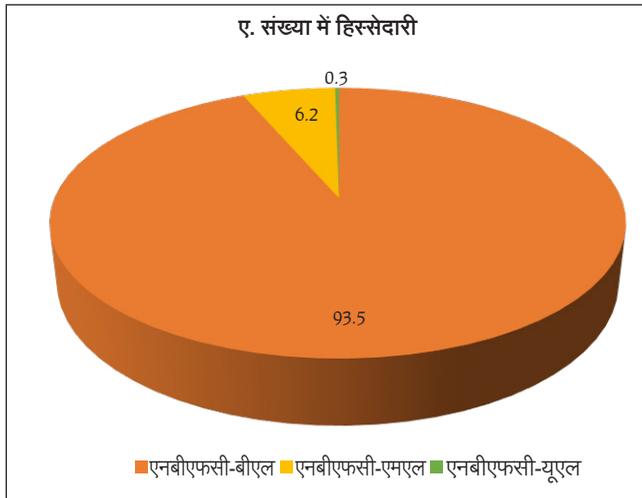
**चार्ट 5: एनबीएफसीएस के लिए स्केल-आधारित विनियमन**



**टिप्पणी:** एनबीएफसी-डी, एनबीएफसी-एनडी, एसपीडी, आईडीएफ, सीआईसी, एचएफसी, आईएफसी, पी2पी, एए, एनओएफएचसी क्रमशः जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी, जमा न लेने वाली एनबीएफसी, एकल प्राथमिक व्यापारी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, मूल निवेश कंपनी, आवास वित्त कंपनी, इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, पीयर-टू-पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म, अकाउंट एग्रीगेटर, नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी को संदर्भित करते हैं।  
**स्रोत:** आरबीआई

एनबीएफसी ने आस्ति आकार में 95 प्रतिशत का योगदान दिया, रिजर्व बैंक ने विवेकपूर्ण रूप से एनबीएफसी-यूएल और एनबीएफसी-एमएल के लिए उत्तरोत्तर कड़े विनियम बनाए।

**चार्ट 6: एनबीएफसी का वितरण (मार्च 2022 के अंत में)**



**टिप्पणी:** सीआईसी, पीडी और एचएफसी सहित।

**स्रोत:** भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2021-22।

#### IV. एनबीएफसी क्षेत्र का तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) आधारित विश्लेषण

31 मार्च 2023 तक, रिज़र्व बैंक के साथ 9443 एनबीएफसी<sup>3</sup> पंजीकृत थे। हालांकि, यह विश्लेषण 205 कंपनियों के नमूने पर आधारित है, जिन्होंने दिसंबर 2020 से दिसंबर 2022 तक सभी तिमाहियों में नियमित रूप से रिटर्न दाखिल किया है। ईएक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) प्लेटफॉर्म पर नमूना<sup>4</sup> दिसंबर 2022 के अंत में एनबीएफसी के समूचे क्षेत्र (आस्तित्व आकार के संदर्भ में) के लगभग 91 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। इस क्षेत्र की समेकित बैलेंस शीट, एक वर्ष पहले की तुलना में दिसंबर 2022 के अंत में दहाई अंकों के स्तर पर बढ़ी, हालांकि वृद्धि की गति कम ही रही (सारणी 2)।

##### IV.1 एनबीएफसी की देयता संरचना

एनबीएफसी मुख्य रूप से बाजार और बैंकों से उधार के माध्यम से अपने परिचालन का वित्तपोषण करती हैं, जो उनकी कुल उधारी का लगभग 75 प्रतिशत है। यह उन्हें सबसे बड़ा

निवल उधारकर्ता बनाता है और परिणामस्वरूप, वे शेष वित्तीय प्रणाली से जटिल रूप से जुड़े हुए हैं (आरबीआई, 2022)। आकलन अवधि के दौरान, निम्न ब्याज स्थितियाँ और मौद्रिक नीति संचरण में पिछड़ने के कारण बैंकों पर एनबीएफसी की निर्भरता लगातार बढ़ी (चार्ट 7ए)। जबकि एनबीएफसी-यूएल सुरक्षित उधारों पर बहुत अधिक निर्भर होता है, एनबीएफसी-एमएल असुरक्षित साधनों के माध्यम से काफी उधार लेता है (चार्ट 7बी)। यह विशेष रूप से बड़ी, सरकारी एनबीएफसी के लिए सच है, जिनकी दो-तिहाई से अधिक उधारी असुरक्षित है। एनबीएफसी-डी (जमाराशि स्वीकार करने वाले एनबीएफसी) की भी सार्वजनिक जमाराशि तक पहुंच है। ये सावधि जमा हैं, जिनमें एक वर्ष पहले की तुलना में दिसंबर 2022 के अंत में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई।

एक गहन विश्लेषण से पता चलता है कि उच्च स्तर में शामिल एनबीएफसी को ऋण देने में बैंकों की प्राथमिकता है। हाल की तिमाहियों में एनबीएफसी-यूएल द्वारा प्रत्यक्ष बैंक उधार लगातार बढ़े हैं, जो दिसंबर 2022 के अंत में उनकी कुल उधारी का लगभग

#### सारणी 2: एनबीएफसी की समेकित बैलेंस शीट

(₹ करोड़)

	माह के अंत में बकाया राशि				वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	
	दिसं-20	दिसं-21	मार्च-22	दिसं-22	(प्रतिशत)	
					21 दिसंबर से 20 दिसंबर तक	22 दिसंबर से 21 दिसंबर
1. शेयर पूंजी	88.849	94.554	96.747	1.01.631	6.4	7.5
2. आरक्षित निधियां और अधिशेष	4.61.941	6.38.539	6.60.596	7.21.029	38.2	12.9
3. सार्वजनिक जमाराशियां	95.911	94.641	96.596	1.15.874	-1.3	22.4
4. कुल उधारियां	20.49.057	23.21.965	24.18.634	26.65.136	13.3	14.8
5. वर्तमान देयताएं और प्रावधान	1.90.311	1.98.130	1.87.864	2.03.939	4.1	2.9
6. अन्य देयताएं	26.187	55.029	56.236	54.606	110.1	-0.8
<b>कुल देयताएं/ आस्तियां</b>	<b>29.12.256</b>	<b>34.02.860</b>	<b>35.16.673</b>	<b>38.62.215</b>	<b>16.8</b>	<b>13.5</b>
1. ऋण और अग्रिम	22.90.297	25.69.452	26.54.006	29.23.955	12.2	13.8
2. निवेश	3.20.506	4.74.099	4.86.340	5.14.189	47.9	8.5
3. नकद एवं बैंक में जमाराशि	1.32.290	1.43.266	1.45.117	1.45.072	8.3	1.3
4. अन्य चालू आस्तियां	99.370	1.00.805	1.07.806	1.30.636	1.4	29.6
5. अन्य आस्तियां	69.794	1.15.238	1.23.404	1.48.364	65.1	28.7

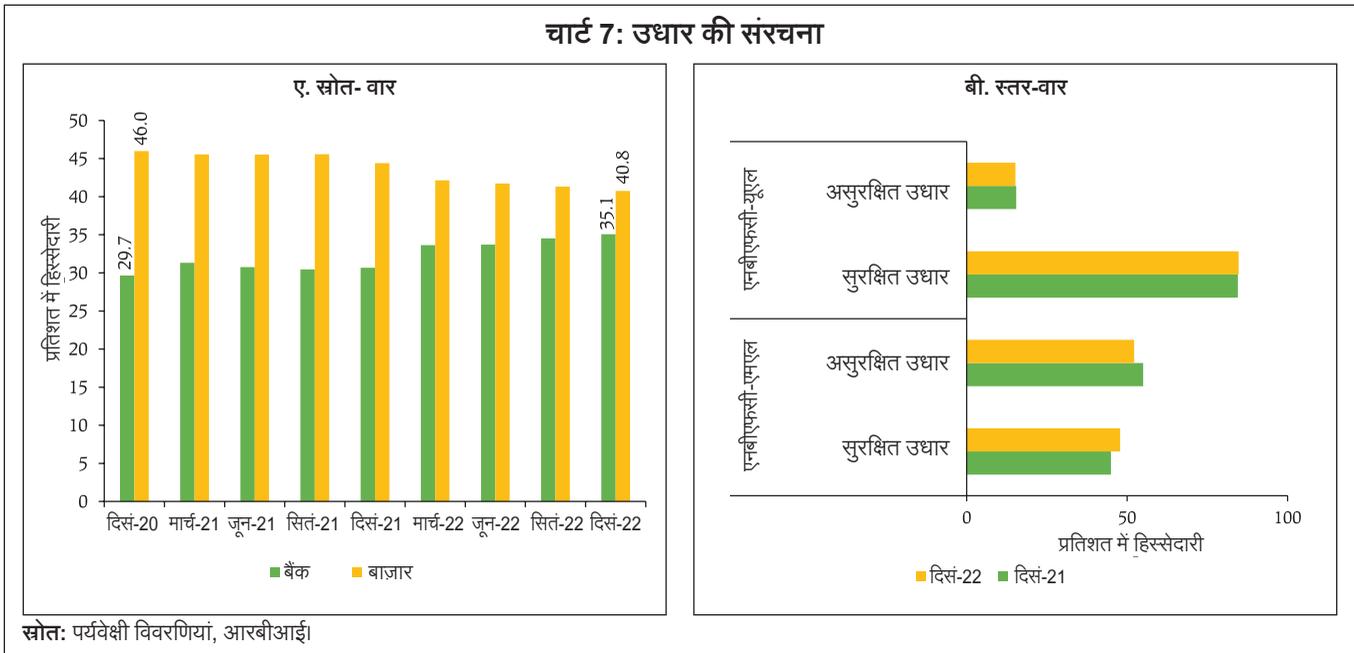
टिप्पणियाँ: 1. डेटा अनंतिम हैं।

2. यहां सभी घटक रिपोर्ट नहीं किए जाने से हो सकता है कि संख्याएं सुसंगत न हों।

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई।

<sup>3</sup> एचएफसी और एआरसी को छोड़कर।

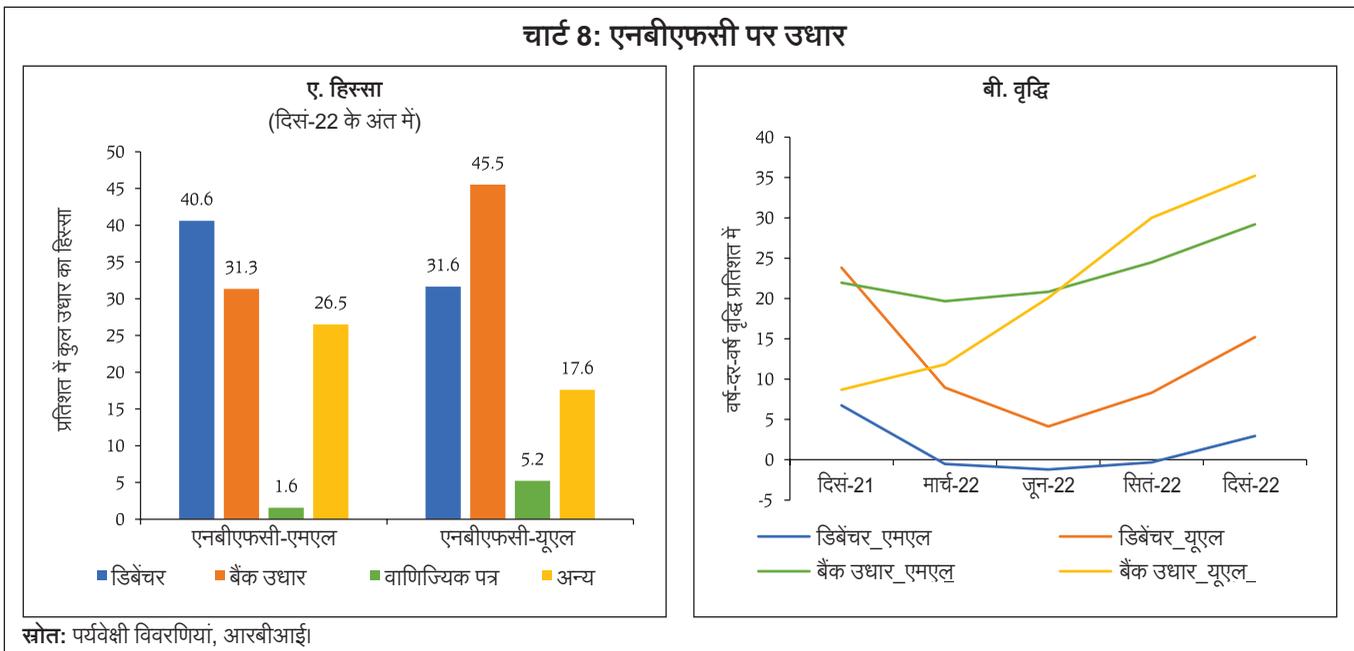
<sup>4</sup> इसमें 10 एनबीएफसी-यूएल शामिल हैं तथा सीआईसी और पीडी को छोड़कर बाकी एनबीएफसी-एमएल हैं। सीआईसी को अगले खंड में शामिल किया गया है।

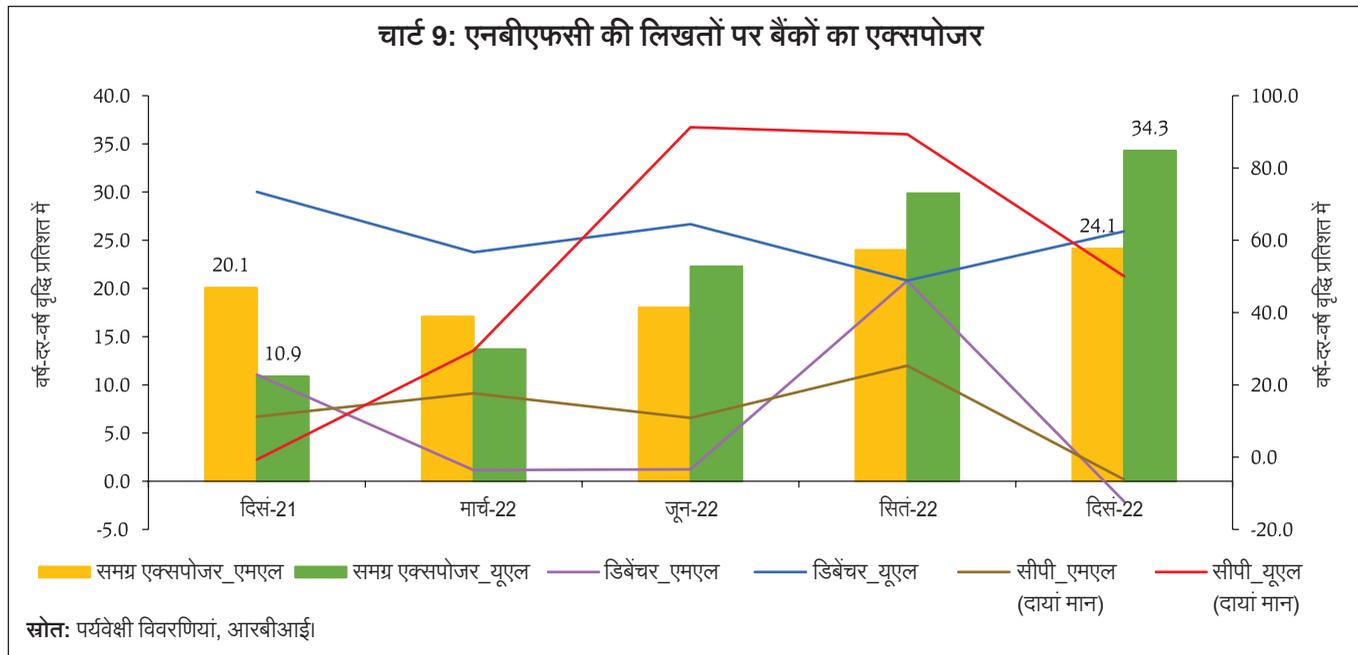


आधा हिस्सा है। एनबीएफसी-एमएल डिबेंचर जारी करने पर अधिक भरोसा करती है, हालांकि हालिया समय में उनकी बैंक उधारी भी बढ़ी है। इसके अलावा, एनबीएफसी-यूएल, वाणिज्यिक पत्र (सीपी) के माध्यम से अल्पकालिक कर्ज लेने में अधिक सफल प्रतीत होता है (चार्ट 8ए और बी)।

प्रत्यक्ष ऋण के अलावा, बैंक एनबीएफसी द्वारा डिबेंचर और सीपी जारी करने के प्रमुख अभिदाताओं में से एक हैं। इस तरह,

एनबीएफसी क्षेत्र में उनका एक्सपोजर प्रत्यक्ष ऋण द्वारा इंगित मात्रा से अधिक है। मुख्य रूप से 2022-23 (दिसंबर 2022 तक) में इन एनबीएफसी के प्रत्यक्ष ऋण में भारी वृद्धि, विशेष रूप से एनबीएफसी-यूएल में, के कारण बैंकों का एक्सपोजर लगातार बढ़ रहा है। एनबीएफसी-यूएल के डिबेंचर और सीपी जारी करने के लिए बैंक सदस्यता भी मजबूत गति से बढ़ रही है, जो बड़े एनबीएफसी की लिखतों के लिए बैंकों की प्राथमिकता को दर्शाती

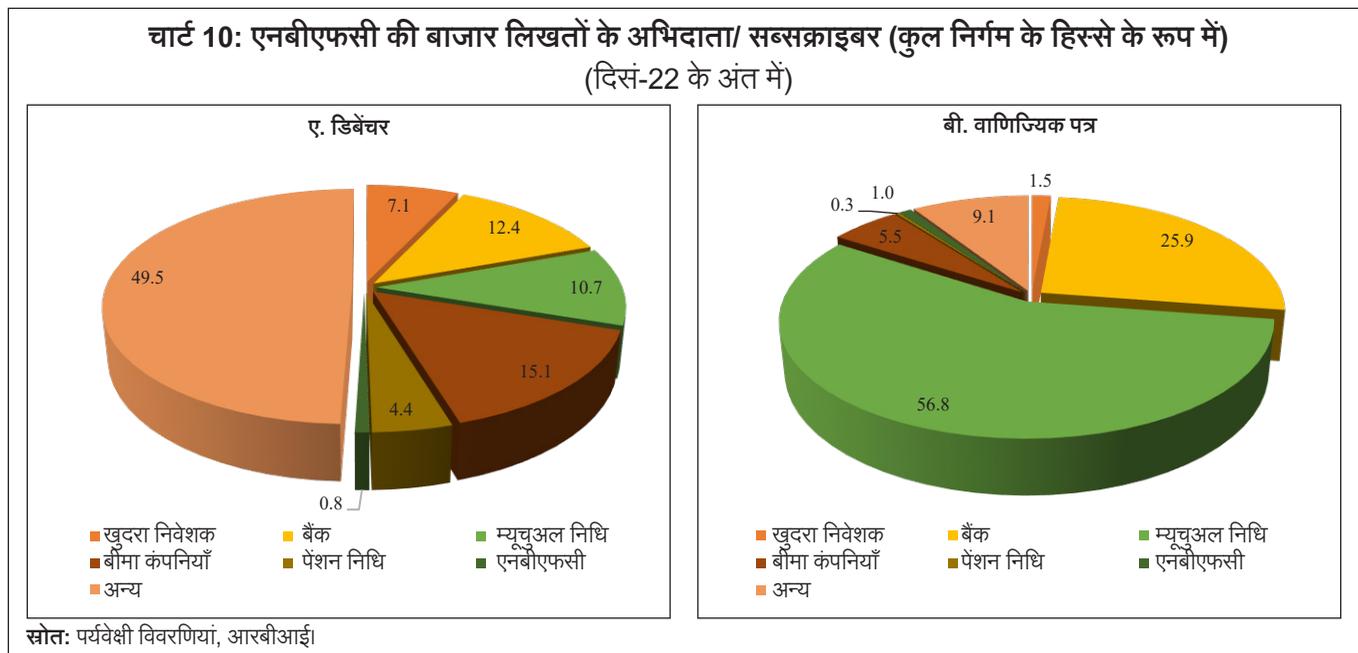




है, जिनके पास सामान्य रूप से मजबूत परेन्टेज हैं और वे बढ़े हुए विनियमन के अधीन हैं (चार्ट 9)।

बैंकों के अलावा कई अन्य बाजार प्रतिभागियों द्वारा भी एनबीएफसी के डिबेंचर निर्गम सब्सक्राइब किए जाते हैं, जिसमें

म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां, खुदरा निवेशक और पेंशन निधि अन्य प्रमुख भागीदार हैं (चार्ट 10ए)। एनबीएफसी के सीपी बाजार में म्यूचुअल फंड और बैंकों का वर्चस्व है, जिसमें से एमएफ की हिस्सेदारी प्रमुख है (चार्ट 10बी)।



### IV.2 एनबीएफसी की आस्ति संरचना

ऋण और अग्रिम एवं निवेश आस्ति पक्ष के शीर्ष दो घटक हैं, जिनके पास कुल आस्ति आकार का क्रमशः 76 और 14 प्रतिशत हिस्सा है। दिसंबर 2022 के अंत में कुल ऋण और अग्रिम 13.8 प्रतिशत की दर से बढ़े, जो एक साल पहले की तुलना में अधिक है। ये ऋण प्रमुखतः सुरक्षित हैं और लंबी परिपक्वता अवधि वाले हैं (चार्ट 11ए और बी)। ऋण और अग्रिम के विपरीत निवेश ने उसी अवधि के दौरान मंद वृद्धि का अनुभव किया।

### IV.3 क्षेत्रवार ऋण

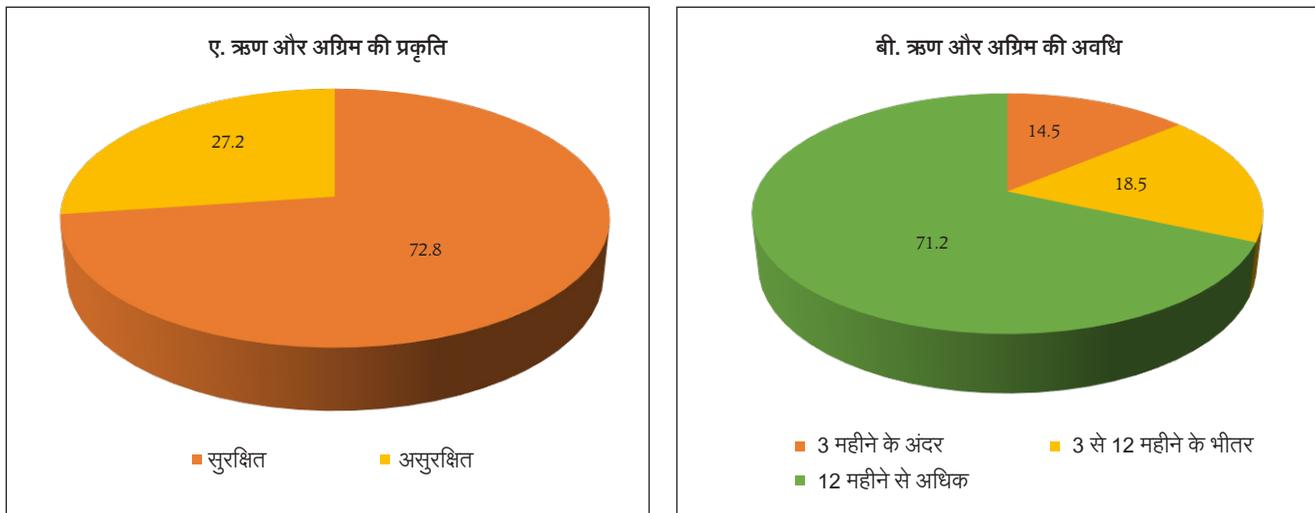
विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में निधियाँ परियोजित करने में बैंकों के पूरक के रूप में एनबीएफसी भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने संबंधित श्रेयों के अवरोही क्रम में, एनबीएफसी क्षेत्र ने दिसंबर 2022 के अंत में उद्योग, खुदरा, सेवाओं और कृषि क्षेत्र को वित्त प्रदान किया (चार्ट 12ए)। महामारी के बाद व्यय में कमी की अवधि के बाद, दिसंबर 2022 के अंत में सकल अग्रिम दहाई अंकों की दर से

बढ़ा, जिसका मुख्य कारण खुदरा और सेवा क्षेत्रों में वृद्धि थी (चार्ट 12बी)।

ऋण आबंटन के स्केल आधारित विश्लेषण से पता चलता है कि उच्च स्तर में शामिल एनबीएफसी (सभी निजी स्वामित्व वाले) खुदरा खंड को अपने सकल अग्रिम का एक बड़ा हिस्सा प्रदान करते हैं, जबकि मध्य स्तर ने उद्योग को अधिकतम ऋण प्रदान किया। मध्य स्तर में आने वाले सरकारी एनबीएफसी, उद्योगों के इंफ्रास्ट्रक्चर खंड में ऋण के बड़े प्रदाता हैं (सारणी 3)।

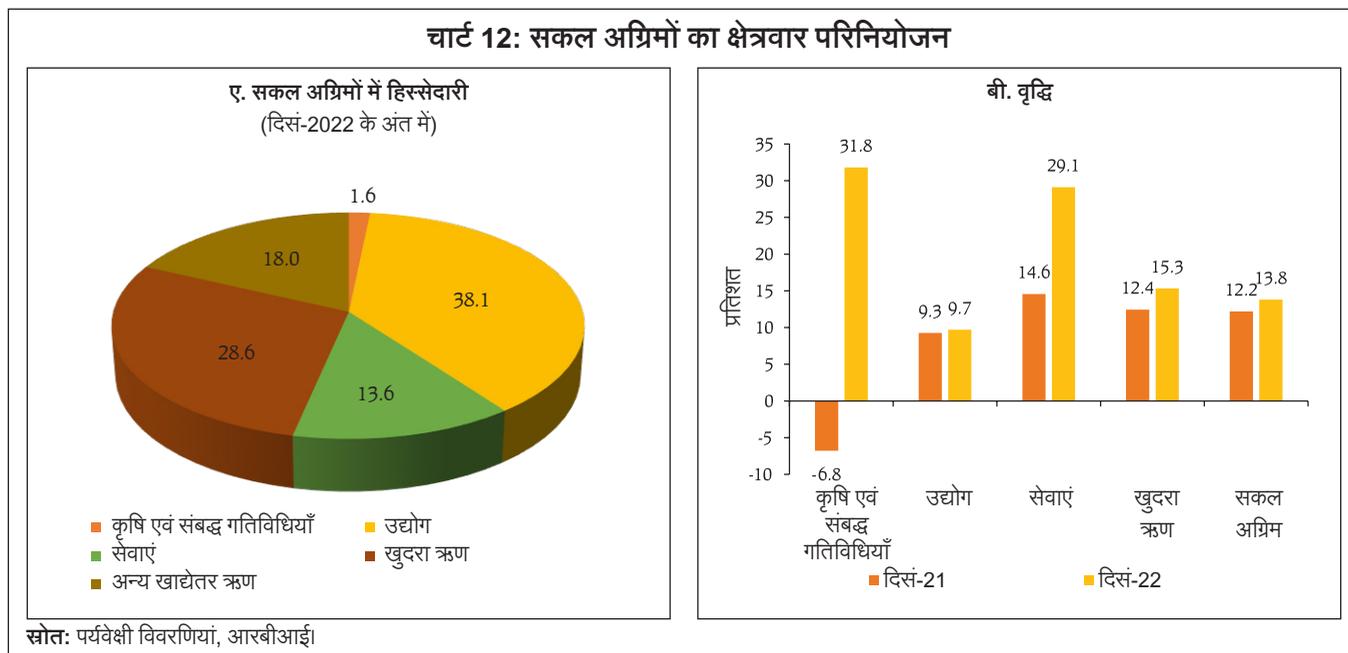
ऐतिहासिक रूप से, एनबीएफसी बैंक रहित/ कम-बैंक सुविधा वाले क्षेत्रों को अग्रिम प्रदान कर रही हैं और वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को आगे बढ़ा रही हैं। उद्योग और सेवा क्षेत्रों के भीतर, एनबीएफसी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अपने बकाया सकल अग्रिमों का लगभग सात प्रतिशत को दिया, जो दिसंबर 2021 के अंत की तुलना में दिसंबर 2022 के अंत में काफी बढ़ गया। खुदरा खंड में, सकल अग्रिम में अपनी हिस्सेदारी के मामले में वाहन ऋण और स्वर्ण पर ऋण ने क्रमशः लगभग 12 और 4 प्रतिशत के साथ शीर्ष दो स्थानों पर रहे।

**चार्ट 11: एनबीएफसी द्वारा ऋण और अग्रिम की विशेषताएं**  
(दिसं-22 के अंत में)



स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई

चार्ट 12: सकल अग्रिमों का क्षेत्रवार परिणियोजन



#### IV.4 वित्तीय प्रदर्शन, आस्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता

एनबीएफसी मुख्य रूप से अपनी निधियों के आबंटन के माध्यम से आय उत्पन्न करते हैं। दूसरी ओर शुल्क आधारित आय, उनकी कुल आय में केवल दो प्रतिशत योगदान देती है। व्यय के पक्ष में, ब्याज व्यय, परिचालन व्यय और अशोध्य ऋणों को बढ़े खाते में डालने पर किए गए व्यय का कुल व्यय में प्रमुख योगदान है। 2022-23 की तीसरी तिमाही के दौरान, एनबीएफसी-यूएल के लिए कुल व्यय का सबसे बड़ा घटक परिचालन व्यय था। दूसरी ओर, कुल व्यय में ब्याज व्यय का हिस्सा उच्च स्तर की तुलना में मध्य स्तर के लिए अधिक था।

आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए), इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) और निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) द्वारा इंगित

**सारणी 3: एनबीएफसी द्वारा क्षेत्रवार ऋण आबंटन का हिस्सा (दिसंबर 2022 के अंत में)**

	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	उद्योग	सेवाएं	खुदरा ऋण	अन्य गैर-खाद्येतर ऋण
उच्च स्तर (10)	3.9	11.4	21.5	62.2	0.9
मध्य स्तर (195)	0.6	49.3	10.3	14.4	25.2

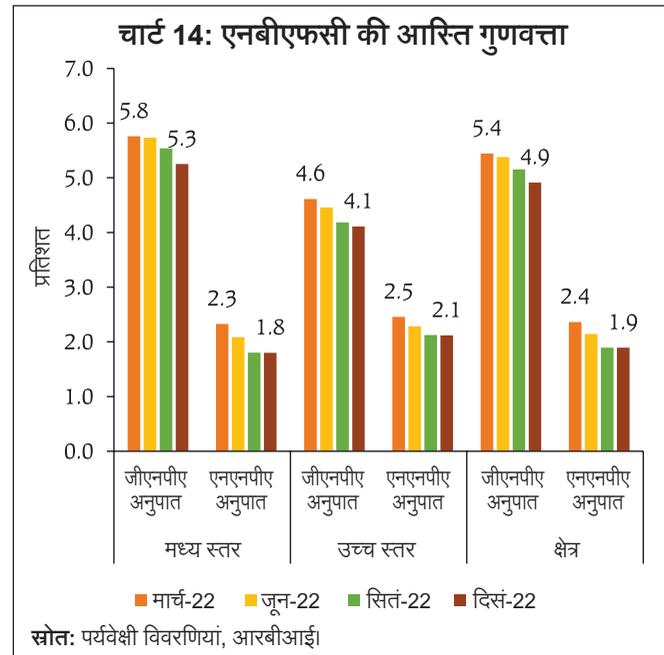
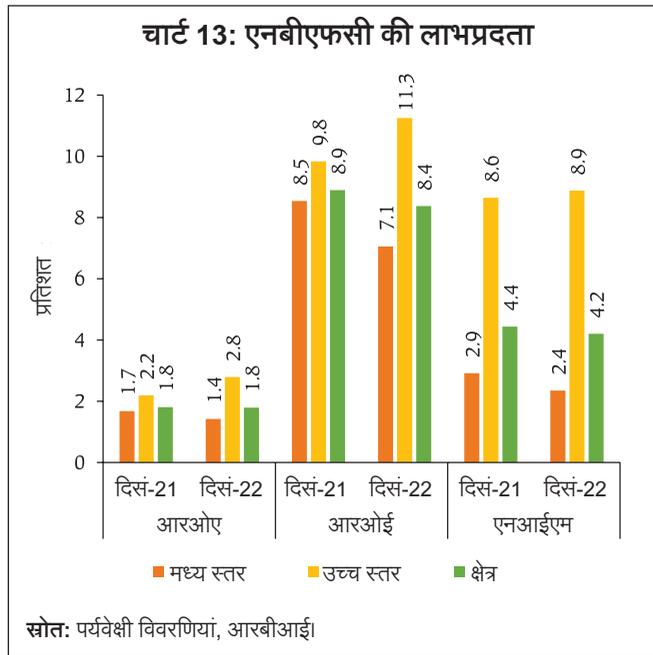
टिप्पणी: कोष्ठक में संख्याएँ एनबीएफसी की संख्या दर्शाती हैं।

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां, आरबीआई

लाभप्रदता सभी स्तरों में भिन्न होती है। क्षेत्र के स्तर पर, आरओए को छोड़कर सभी लाभप्रदता संकेतकों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2022-23 की तीसरी तिमाही में कुछ कमी आयी। दूसरी ओर, उसी अवधि में मूल्यांकन किए जाने पर उच्च स्तर का प्रदर्शन बेहतर रहा (चार्ट 13)।

बेहतर समुत्थान प्रथाओं और आर्थिक गतिविधियों की बहाली से ऋण को समय पर चुकाने में मदद मिली। दिसंबर 2022 के अंत में जीएनपीए और एनएनपीए अनुपात में कमी, इस क्षेत्र के लिए अच्छा संकेत है (चार्ट 14)। यह गिरावट मुख्य रूप से कम अभिवृद्धि, बेहतर रिकवरी और राइट-ऑफ के कारण आई थी।

समग्र स्तर पर एनबीएफसी क्षेत्र ने पर्याप्त पूंजी बनाए रखी, क्योंकि जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) 25.8 प्रतिशत था, जो दिसंबर 2022 के अंत में 15 प्रतिशत की विनियामक आवश्यकता से काफी अधिक था। निम्नतर डिफॉल्ट जोखिम के साथ उच्च सीआरएआर मजबूत वित्तीय स्थिति का संकेत है। एसबीआर के तहत, एनबीएफसी-एमएल और एनबीएफसी-यूएल को अपने जोखिमों का वास्तविक आकलन करना और तदनुसार अपनी पूंजी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना आवश्यक है। यह आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) के अनुरूप किया जाना चाहिए, जो बासेल III विनियमों के स्तंभ 2 के तहत वाणिज्यिक बैंकों के



लिए निर्धारित है, हालांकि, एनबीएफसी के लिए जोर नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एनबीएफसी-यूएल को जोखिम-भारित आरिस्तियों के कम-से-कम नौ प्रतिशत की सामान्य इक्विटी टियर - I पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता होती है।

वर्ष 2018 में आईएल एंड एफएस संकट के बाद से इस क्षेत्र की बैलेंस शीट मजबूत वित्तीय स्थिति के साथ बढ़ रही है। यह संकट एक बड़े सीआईसी की समूह कंपनी द्वारा अपनी अल्पकालिक देयताओं पर चूक के कारण सामने आया, जिससे प्रणाली में चलनिधि आघात देखने को मिला। म्यूचुअल फंड जो सीपी बाजार में एक बड़े भागीदार थे और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश रखते थे, ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और एनबीएफसी में अपना निवेश कम कर दिया (कुलकर्णी, नीलिमा, और सिन्हा, 2023)। दिसंबर 2022 के अंत में, म्यूचुअल फंड फिर से एनबीएफसी द्वारा जारी सीपी के सबसे बड़े ग्राहक बन गए हैं, जो उनके व्यवसायों में बाजार के विश्वास की वापसी को दर्शाता है। इस घटना के आलोक में, अगला खंड सीआईसी की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालता है।

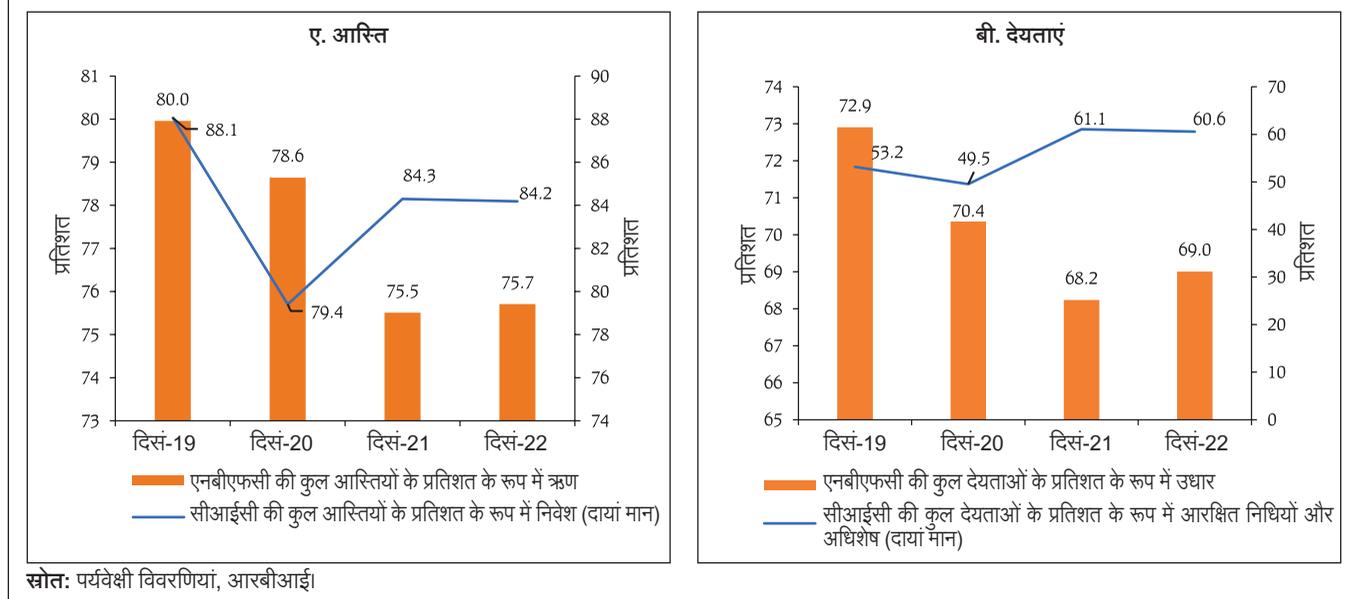
## V. मूल निवेश कंपनियों

मूल निवेश कंपनियां (सीआईसी) एनबीएफसी जगत के भीतर एक विशिष्ट खंड हैं जो प्रवर्तकों को समूह की कंपनियों में हिस्सेदारी रखने का अवसर प्रदान करती हैं। वर्ष 2002 में

सीआईसी को निवेश कंपनियों के रूप में निर्धारित किया गया था, जिनका एकमात्र व्यवसाय समूह की कंपनियों में निवेश करना था। इसके बाद, सीआईसी द्वारा समूह कंपनियों की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के दायरे को सीमित करने के लिए, 2010 में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण सीआईसी (सीआईसी-एनडी-एसआई) नामक एक श्रेणी शुरू की गई थी। इस प्रकार, डिजाइन के अनुसार, सीआईसी को समूह की कंपनियों में निवेश करने के लिए अनिवार्य किया गया था, जो बदले में उनके निवेश को सीमित करते थे। इसलिए, अन्य एनबीएफसी के लिए लागू होने वाले विशिष्ट विवेकपूर्ण मानदंड, जो मुख्य रूप से उधार देने से संबंधित हैं और सीआईसी के कारोबार मॉडल के अनुरूप थे, सीआईसी पर लागू हो गए, जो उनके कारोबार मॉडल के अनुरूप थे (आरबीआई, 2019)। इस प्रकार, उन्हें केवल समायोजित निवल मालियत (एएनडब्ल्यू) बनाए रखने की आवश्यकता थी ताकि यह उनके समग्र जोखिम भारित आरिस्तियों का कम-से-कम 30 प्रतिशत हो, साथ ही लीवरेज अनुपात उनके एएनडब्ल्यू के 2.5 गुना से अधिक न हो। इसके अलावा, सीआईसी के लिए प्रमुख व्यावसायिक मानदंडों में समूह की कंपनियों के लिए न्यूनतम 90 प्रतिशत का एक्सपोजर<sup>5</sup> अनिवार्य है, जिसमें से 60 प्रतिशत इक्विटी निवेश के रूप में होनी चाहिए (आरबीआई, 2022)।

<sup>5</sup> समूह कंपनियों में ऋण और निवेश दोनों शामिल हैं।

**चार्ट 15: सीआईसीएस की आस्ति और देयताएं**



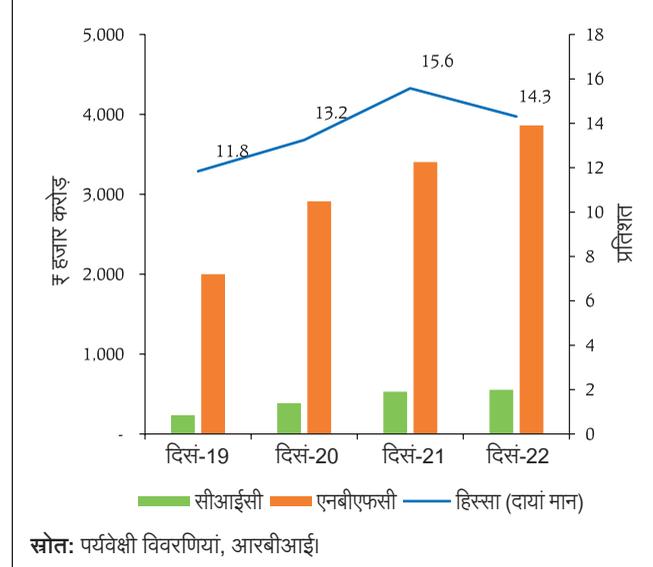
चूंकि सीआईसीएस की व्यावसायिक गतिविधि मुख्यतः निवेश रही है, इसलिए समूह की कंपनियों में उनका निवेश दिसंबर 2022 के अंत में कुल आस्तियों का 84.2 प्रतिशत था, जबकि एनबीएफसी के लिए इसी अवधि के दौरान ऋण और अग्रियों की हिस्सेदारी सबसे अधिक 75.7 प्रतिशत थी (चार्ट 15)। सीआईसीएस के लिए देयता पक्ष पर, आरक्षित निधि और अधिशेष सबसे बड़े घटक थे, जो उनकी कुल आस्तियों का 60.6 प्रतिशत हिस्सा थे, जबकि एनबीएफसी के लिए इसी अवधि के दौरान उधार उनकी कुल आस्ति का 69 प्रतिशत हिस्से वाला सबसे बड़ा घटक था (चार्ट 15बी)।

इसके अलावा, केवल दिसंबर 2022 में गिरावट को छोड़कर एनबीएफसी की बैलेंस शीट के अनुपात के रूप में सीआईसीएस की बैलेंस शीट का आकार धीरे-धीरे बढ़ रहा है, जो सीआईसीएस के बढ़ते महत्व को दर्शाता है (चार्ट 16)।

भारतीय वित्तीय प्रणाली पर 2018 के आईएल एंड एफएस प्रकरण का बड़ा प्रभाव पड़ा और सीआईसीएस द्वारा उत्पन्न प्रणालीगत जोखिम को उजागर किया। हालांकि, सरकार और रिज़र्व बैंक के यथासमय मध्यक्षेप से भरोसा बहाल हुआ। तपन रे समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए थे, जिनका उद्देश्य जटिल समूह संरचनाओं और वित्तीय प्रणालियों के साथ सीआईसीएस के परस्पर संबंध की

निगरानी करना तथा उनके लिए कॉर्पोरेट अभिशासन ढांचे को सुदृढ़ बनाना था। नए दिशानिर्देशों के तहत, एएनडब्ल्यू की परिभाषा को कई बार गियरिंग और अत्यधिक लाभ उठाने के मुद्दों को संबोधित करने के लिए बदल दिया गया था। अब, जैसा कि अन्य एनबीएफसी पर लागू होता है, सीआईसीएस द्वारा स्टेप-डाउन सीआईसीएस में अपनी स्वाधिकृत निधियों के 10 प्रतिशत से अधिक पूंजीगत योगदान को उसके एएनडब्ल्यू से घटा दिया जाता है।

**चार्ट 16: एनबीएफसी की आस्तियों के अनुपात के रूप में सीआईसीएस की आस्तियां**



इसके अलावा, समूह संरचनाओं में जटिलता और एक समूह के भीतर कई सीआईसी के अस्तित्व को संबोधित करने के लिए, एक समूह (मूल सीआईसी सहित) के भीतर सीआईसी के स्तरों की संख्या को दो तक सीमित कर दिया गया है। समूह जोखिम प्रबंधन समिति (जीआरएमसी) को समूह स्तर पर उच्च लीवरेज और अन्य जोखिमों के निर्माण के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अधिदेशित किया गया है। ₹5,000 करोड़ से अधिक की आस्ति वाले सीआईसी को भी मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता होती है। पारदर्शिता बढ़ाने और उचित जांच-पड़ताल करने के लिए और अधिक कॉरपोरेट गवर्नेंस और प्रकटीकरण निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, सीआईसी को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार एक समेकित वित्तीय विवरणी तैयार करनी होगी, ताकि समूह की वित्तीय स्थिति के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान किया जा सके। गलत बयानी की गुंजाइश को कम करने के लिए, जिन सीआईसी को रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें अब "छूट प्राप्त सीआईसी" के बजाय "अपंजीकृत सीआईसी" कहा जाएगा<sup>6</sup>

आगे चलकर, संशोधित दिशानिर्देशों से वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव डालने वाली विफलता की संभावनाओं को कम करके इस क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने की उम्मीद है।

## VI. निष्कर्ष

नवोन्मेष और गतिशीलता विश्व स्तर पर एनबीएफसी क्षेत्र की पहचान हैं। ईई के विपरीत, भारत में एनबीएफसी उधारदाताओं और उधारकर्ताओं के बीच अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं। यद्यपि एनबीएफसी क्षेत्र की बैलेंस शीट का आकार एससीबी के पांचवें हिस्से के बराबर भी नहीं है, यह भारतीय वित्तीय परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने में बैंकों का पूरक है। इन वर्षों में, कई एनबीएफसी विकसित हुए हैं और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण हो गए हैं और इस संदर्भ में, स्केल-आधारित विनियमन प्रासंगिक और सामयिक, दोनों हैं। 2022-23 की तीसरी तिमाही के अंत में, एनबीएफसी क्षेत्र की समेकित बैलेंस शीट ने दहाई अंकों की वृद्धि का प्रदर्शन किया। महामारी के बाद आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने के कारण इस क्षेत्र के जीएनपीए और

एनएनपीए अनुपात में कम अभिवृद्धि, बेहतर रिकवरी और राइट-ऑफ की वजह से कमी आई है। इस क्षेत्र ने पर्याप्त प्रावधान और मजबूत पूंजी बफर बनाए रखना जारी रखा है।

हाल के वर्षों में, एनबीएफसी तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल ऋण क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं, व्यापक दर्शकों तक पहुंचने और उपयोगकर्ता अनुभव को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहे हैं। डिजिटल चैनलों के माध्यम से 5.6 प्रतिशत ऋण मंजूर करने वाले बैंकों की तुलना में, एनबीएफसी ने 2019-20 में 60 प्रतिशत ऋण डिजिटल रूप से स्वीकृत किए (आरबीआई, 2021)। इस गति से चलते हुए, नए युग की एनबीएफसी व्यावसायिक प्रक्रियाओं और निर्णय लेने में सुधार के लिए अपने परिचालन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/ मशीन लर्निंग (एआई/ एमएल) टूल को एकीकृत कर रही हैं। रिज़र्व बैंक भी एनबीएफसी को निर्बाध ग्राहक इंटरफेस के लिए डिजिटल समाधान अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है। इस संबंध में, रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी-यूएल और एनबीएफसी-एमएल को 10 या अधिक निश्चित बिंदु सेवा वितरण इकाइयों के साथ बैंकों द्वारा अपनाए गए कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) की तरह 30 सितंबर 2025 को या उससे पहले 'कोर फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशन (सीएफएसएस)' को लागू करने के लिए अनिवार्य किया है<sup>7</sup>

आगे आने वाले समय में, एनबीएफसी को अपने वित्त पोषण स्रोतों में विविधता लाने की आवश्यकता है, जिससे बैंक उधार पर उनकी अत्यधिक निर्भरता कम हो सके। उन्हें सुदृढ़ अभिशासन और जोखिम प्रबंधन मानकों को विकसित करने और साइबर अपराधों के बारे में अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बढ़ता डिजिटल ऋण क्षेत्र विशाल अवसर प्रदान करने के साथ-साथ नई चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है।

## संदर्भ

Aldasoro, I., Huang, W., & Kemp, E. (2020). Cross-border links between banks and non-bank financial institutions. *BIS Quarterly Review*.

Aramonte, S., Schrimpf, A., & Shin, H. S. (2022). Non-bank financial intermediaries and financial stability. *BIS Working Papers No. 972*.

<sup>6</sup> <https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11949&Mode=0>

<sup>7</sup> <https://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=12247&Mode=0>

FSB. (2022). *Global Monitoring Report on Non-Bank Financial Intermediation*. Financial Stability Board.

Kannan, R., Shanmugam, K. R., & Bhaduri, S. (2019). *Non-Banking Financial Companies Role in India's Development*. Springer.

Kulkarni, N., Neelima, K. M., & Sinha, S. (2023, August 29). Anatomy of a Liquidity Shock on Non-banks. CAFRAL, Working Paper.

MFIN. (2022). *Micrometer*. MicroFinance Institutions Network.

RBI. (2019). *Report of the Working Group to Review the Regulatory and Supervisory Framework for Core Investment Companies*. Reserve Bank of India.

RBI. (2021). *Report of the Working Group on Digital Lending including Lending through Online Platforms and Mobile Apps*. Reserve Bank of India.

RBI. (2022). *Financial Stability Report*. Reserve Bank of India.

RBI. (2022). Master Direction - Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016.